राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग्)( )नियम/डीएलबी/18/820-826 जयपुर,दिनांकः 25/7/18

आयुक्त,
समस्त, नगर निगम,
राजस्थान।

विषयः वार्ड समितियों का गठन करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 54 के प्रावधानानुसार 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समिति गठित करने का आज्ञापक प्रावधान है। अधिनियम की धारा 54 (1), (2), (3), (4) निम्नवत् है:–

54. Constitution of Wards Committee.-(1) There shall be constituted Wards Committees, consisting of one or more wards, within the territorial areas of the Municipalities having population of three lakh or more.

(2) Each Ward Committee shall consist of & (a) the members of the Municipality representing the wards within the territorial areas of the Wards Committee; and

(b) such other members, not exceeding five who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the Municipality :

Provided that a person shall be disqualified for being nominated , and for being , a member of the Wards Committee, if under the provision of this Act or any other law for the time being in force, he would be disqualified for being elected as, and for being, a member.

(3) Where a Wards Committee consists of one ward, the member representing that ward in the municipality shall be the Chairperson of that Committee.

(4) (a) The Ward Committee shall at its first meeting after its constitution under sub-section (1) and at its first meeting in the same month in each succeeding year shall elect where the Wards Committee consists of two or more wards, one of the members representing such wards in the Municipality to be the Chairperson of that Committee.

(b) The Chairperson shall hold office until his successor has been elected and shall be eligible for reelection.

अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार सभी नगर निगमो को वार्ड समितियों का गठन कर धारा 60 के प्रावधानानुसार वार्ड समितियों के सामान्य कृत्य निर्वहन करेगी।

अतएव सभी नगर निगमो की साधारण सभा में वार्ड समितियों के गठन का प्रस्ताव रखकर वार्ड समितियों का गठन करना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग्)()नियम/डीएलबी/18/827-833 जयपुर,दिनांकः 25/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त महापौर, नगर निगम राजस्थान।
2. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी